thing that can be contemplated in this category is tobacco. If you are taxing tobacco, the exchequer will be benefited more. Tax evasion will be minimum. So, instead of bidi, let us switch over to tobacco for purposes of excise duty Finally, so far as the Gujarat calamity fund is concerned, we are taking one rupee per day from each of the workers. It is still continuing. One rupee per day comes to about 25 or 26 rupees per month per worker These workers are getting just the Minimum Wages, or, at times, even less then that. This should be looked into very seriously. We have to stop deducting this. This will be beneficial to the bidi workers. I feel the hon. Minister should make categorical assurances on each of the points that I have put forward.

MESSAGE FROM LOK SABHA

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is a message from Lok Sabha. Secretary-General.

The Weapons of Mass Destruction and their delivery systems (Prohibition of Unlawful Activities) Bill, 2005

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Bill, 2005, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 12th May, 2005 "

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Points arising out of answer given in Rajya Sabha on 5th May, 2005 to Starred Question No. 589 Regarding 'Minimum Wages to Beedi Workers'—(Contd.)

श्री उपसभापति: श्री नंदी येल्लैया। आप तीन मिनट में खत्म करें।

श्री नंदी येल्लैया (आंध्र प्रदेश): सर, मेरा यह क्वैश्चन है जिस की वजह से half an hour discussion हो रहा है।

श्री उपसभापति: श्री वी॰ हनुमंत राव ने बहुत कुछ कह दिया है।

श्री नंदी येल्लैया: सर, हनुमंत राव जी ने जो पॉइंट्स नहीं उठाए हैं, मैं उन पर बोलना चाहता हूं।

सर, अभी हमारे दो सदस्यों ने 45 लाख का आंकड़ा दिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। यह 45 लाख तो हमारे केरल के हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के अंदर, हमारे श्रम मंत्री जी बैठे हुए हैं, ये चार बार विधान सभा क्षेत्र सिद्धीपेठ से चुनकर आए हैं और मैं भी 5 बार उसी मेदक डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। मेदक, करीमनगर, निजामाबाद और वारंगल के अंदर काफी बीड़ी बनाने वाले वर्कर्स हैं। अब सवाल यह है कि बीड़ी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनमें ज्यादातर 60 परसेंट मकानों के अंदर बीड़ी बनाते हैं। सर, हमारे माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं और वे जानते हैं कि गरीबी क्या चीज है? उन्होंने प्रश्न काल के अंदर ऑफिसियल तौर पर इस हाउस के अंदर मिनिमम वेजेज 85 रुपए एनाउंस किया, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जैसे मेदक के अंदर जो सौ बीड़ी बनाते हैं, उनको सिर्फ 65 रुपए 5 नए पैसे दिए जा रहे हैं। यह सिद्धीपेठ की हकीकत है। मैंने कल ही बात की है।

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: (श्रम और रोजगार मंत्री): सौ नहीं, हजार पर।

श्री नंदी येल्लैया: हां, हजार बीड़ी के 65 रुपए, 5 नए पैसे दिये जाते हैं और जो गांवों में या Interior Villages में हैं, वहां पर सिर्फ 35 पैसा दिया जाता है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लेबर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत संख्या में इंस्पैक्टर काम करते हैं और उन्हें यह जांच करनी चाहिए कि कितना मिनिमम वेज दिया जा रहा है। वहां अगर फैक्ट्री के अंदर सौ लेबर काम करते हैं तो 50 का रजिस्ट्रेशन दिखाया जाता है। उसके बाद वे लोग चले जाते हैं। दूसरे, जहां तक मुझे मिनिमम वेज की जानकारी है, तीन साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुआ है। इस वजह से मजदूरों का शोषण हो रहा है। मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उनके लिए हाउसिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ही लोगों को हाउसिंग की फेसिलिटी दी जा रही है, जैसे मकान बनाने वाले हैं, पर वहां जो 60 परसेंट बीड़ी मजदूर, मकानों में रहकर काम करते हैं, उनको नजरंदाज किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए। दूसरे, उनका पी॰एफ॰ का हक है। भारत सरकार के कानून के अनुसार इंडस्ट्रियल फील्ड में काम करने वाले मजदूर प्रोवीडेंट फंड के हकदार होते हैं। सर, ये भी मजदूर हैं और ये भी बीड़ी

एक्ट के तहत आते हैं, लेकिन वहां लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, लेबर कमीशन की तरफ से कोई नहीं जाता है। वहां पर ये तमाम नाइंसाफी हो रही है। उनको भी प्रोवीडेंट फंड कवरेज का लाभ मिलना चाहिए।

माननीय डिप्टी-चैयरमेन साहब, ये जो बीड़ी बनाने वाले मजदूर हैं, तंबाकू से उन लोगों को कैंसर की शिकायत हो जाती है, टी॰बी॰ की शिकायत हो जाती है, अस्थमा भी हो जाता है। ये बेचारे गरीब लोग हैं जो इलाज भी नहीं करा सकते हैं। सर, हमारे पास एक बिल पड़ा हुआ है कि हम उनको रिजर्वेशन देने के बारे में सोच रहे हैं। वहां पर इसकी फेसिलिटी नहीं है।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप राज्यों के मिनिस्टरों की एक कंफरेंस बुलाकर मिनिमम वेजेज, सैलरी देने के लिए आप आश्वासन देंगे? दूसरे ...**समय की घंटी**... हमारे हाउसिंग के जो प्रोब्लेम्स हैं, जैसा कि हमारे माननीय श्री हनुमंत राव जी ने कहा, उन्होंने स्कॉलरशिप की बात की। जहां पर उनके बच्चे पढ़ते हैं, वहां उनको भी स्कॉलरशिप की फैसिलिटी होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारे मंत्री महोदय बहुत होशियार आदमी हैं, काबिल आदमी हैं। हर चीज को बड़े अंदाज से बोलते हैं, लेकिन यह गरीबों का मामला है। हमारे लेबर मिनिस्टर साहब, आप जानते हैं कि जिस हल्के से आए ...**(व्यवधान)**... यानी जहां से मैं भी आया हूं, आप भी पांच बार एम॰एल॰ए॰ थे, मैं भी पांच बार लोक सभा में था, अभी मैं राज्य सभा में हूं और आप लोक सभा में हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप श्रम मंत्री होने के नाते, जहां पर नाइंसाफी हो रही है, आप इंसाफ करने के लिए आश्वासन दीजिए और हर राज्य का ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: होशियारी से काम करिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री नंदी येल्लैया: नहीं, ज्यादा होशियारी अच्छी नहीं होती ...**(व्यवधान)**... वे लोग खतरे में घिर जाएंगे, क्योंकि वे लोग बहुत होशियार आदमी हैं। कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, वे अच्छी तरह से जानते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। स्टेट के अन्दर वे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी फर्स्ट टाईम श्रम मंत्री हैं। डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए इनसे निवेदन करना चाहता हूं। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट इश्यू यह है कि यह लेडीज का मामला है। वे गांवों में रहती हैं, गांवों में रहने का उनका दूसरा कोई सहारा ही नहीं रहता है। **(समय की घंटी)** ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: ठीक है।

श्री नंदी येल्लैया: वे उसी पर डिपेंड रहती हैं। मैं आपके जरिए श्रम मंत्री जी से कहूंगा कि मकानों के अलॉटमेंट में, चाहे फैक्टरी में करने वाले हो या मकान में करने वाले, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। दूसरा यह कि इंश्योरेंस में सारे लोगों का कवरेज होना चाहिए। तीसरा यह कि प्रोविडेंट फंड सारे लोगों को मिलना चाहिए। मिनिमम वेजेज का पूरा इम्प्लिमेंटेशन नहीं हो रहा है।

कहीं झारखंड में एक तरफ और दूसरी जगहों में एक तरफ। इसलिए आपका फर्ज है, आपका कर्त्तव्य है कि इसकी पूरी समीक्षा करके सारे राज्यों का एक कॉन्फेरेंस बुलाकर काफी इंसाफ करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपसभापति: धन्यवाद, शुक्रिया। श्री दत्ता मेघे।

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, उस दिन श्री हनुमंत राव जी का बीड़ी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने का जो क्वेश्चन था, उसके बारे में आज चर्चा हो रही है। मैं तो राव साहब को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उस दिन भी जब हमने क्वैश्चन पूछे थे, उसमें भी जवाब दिए थे। लेकिन आज यह सिर्फ आंध्र प्रदेश या किसी स्टेट का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का प्रश्न है। महाराष्ट्र, खास तौर पर विदर्भ, विदर्भ और तेलंगाना बहुत नजदीक-नजदीक हैं। वे तो राज्य बना रहे हैं, हमारा भी राज्य बन जाए, इतनी उनकी बड़ी शक्ति है, हमें मालूम है और यह बीड़ी मजदूरों का काम जिसमें 19 परसेंट से ज्यादा लेडीज़ और साथ ही आजकल छोटे बच्चे भी घर-घर जाकर यह काम करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, उनको यह काम नहीं करने देना चाहिए। 10 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे हैं, हर घर में यह काम होता है। इसलिए बच्चों को इस काम से अलग कर देना चाहिए और जो भी आपका न्यूनतम वेजेज है, बच्चों को तो वह भी नहीं मिलता है। इसमें बड़े-बड़े लोग, सेठ लोग, बड़ी-बड़ी कंपनियां काम करती हैं। हमारे यहां भंडारा हो, गोंडिया हो, चंद्रापुर हो, नागपुर हो, खामगांव हो, सब जगह बहुत-सारे मजदूर बीड़ी का काम करते हैं। इसलिए जो बीड़ी का काम कर रहे हैं, घर में करें या फैक्टरी में करें, उनको कम-से-कम इस कैटेगरी में लाना चाहिए, क्योंकि वे कंटैक्ट पर दे देते हैं, कोई न्यूनतम वेजेज नहीं देते। उनके लिए कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है और न कोई योजना ही उनको मिलती है। इसके बारे में आप जैसा आंध्र में तो खैर देने वाले ही हैं, बिल्कुल वैसा ही हमारे विदर्भ के बीड़ी मजदूरों का भी आपने थोड़ा ख्याल किया। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर गरीब लोगों की मदद होने वाली है। इतना ही है कि छोटे बच्चों को यह काम नहीं करने देना चाहिए और उनको जो भी सुविधा हो, वह लीगली तो नहीं देंगे, उनके ऊपर पैनलाईज करवा दीजिए। बड़े-बड़े सेठ लोग आज इस धंधे में हैं। वे तो फायदे में हैं। बीड़ी के जो रेट हैं, भाव हैं, वे बढ़ रहे हैं। सारी जगह बीड़ी जाती है, चाहे हमारा आसाम हो या दूसरी बड़ी-बड़ी जगहें, जहां कुछ होता नहीं। यह तेंदू-पत्ता जहां होता है, वहां पर बीड़ी का बहुत काम होता है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि जो लोग इसमें सम्मिलित हैं, जो कायदा-कानून है, जैसा आपने कहा न्यूनतम मजदूरी का, यह इन लोगों के लिए पूरे देश में एक होना चाहिए। महाराष्ट्र में अलग हो, विदर्भ में अलग हो और वह भी आधे से ज्यादा लोगों को मिलता नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो उनका हक है, जो स्टेट उनके लिए करेगा, वह सबको मिलना चाहिए। यही मैं दरखास्त करता हूं और राव साहब से हम सब लोगों को उम्मीद है, पूरे देश के कामगारों को उम्मीद है कि आप कोई अच्छी बात यहां कहेंगे और उसका इंपलीमेंटेशन होगा। धन्यवाद।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh). Sir, lakhs of people are involved in beedi making. I know the time constraint and the scope of the debate. . .*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN. The issue is common . .*(Interruptions)*... There is nothing new in that .*(Interruptions)*. .

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY. I would like to draw the attention of the hon Minister to his original answer to Starred Question No 589 on 5th May in this august House He said only 17.96 lakh people are involved and brought under the purview of Act and 4196 establishments are brought under the purview of the Minimum Wages Act. Sir, lakhs of people are working in this industry. According to his own answer, more than 40 lakh people are working in this industry. When are you going to bring all these people under the purview of the Minimum Wages Act? This is number one. Then he has answered to another Unstarred Question that there is disparity in wages in respect of beedi workers from State to State. I would like to know from the hon. Minister about the steps being taken to minimise this disparity in wages ranging from Rs. 31.20 to Rs. 172 84 What are the steps contemplated by the Ministry? Then I am referring to Unstarred Question No. 131, which he has answered in the Lok Sabha. He has answered that there is disparity and that disparity is very huge — Rs. 31 and Rs. 172. What are the steps contemplated by the Ministry? This is number two. As has been stated by many hon. Members there is PF — employee's contribution and the employer's contribution. You have adopted a system called Monitoring Through Computerised Complaint Tracking System — CCTS. I would like to know the details of the system, how it is working and in what way it is useful to the working class. Now, coming to the welfare fund, I would like to know from the hon. Minister how many workers have been provided houses so far and how many have not still been provided houses. Coming to health sector, Sir, as stated by Mr. Nandi Yellaiah, the condition of the people working in the beedi industry is very precarious. If you look at them, you see their eyes sunken. These people are affected by tuberculosis. Their condition is very pathetic. I personally went to many houses. They are working in my own area. Their condition is very precarious. According to his own answer, only six hospitals are there in the country for these people. Sir, for a working

class of more than 50 lakh, there are only six hospitals, which are working in the country, apart from 206 dispensaries. Do you think that it is sufficient for them? They are already poverty-stricken having very poor health condition. These hospitals are not sufficient for them What are the steps taken by the Ministry to improve these hospitals? And not only should you improve the number, but also see to the quality of treatment, medicines provided to them and the money spent on the dispensaries. This is another one Coming to education, I would say that no special treatment is given to the children of beedi workers I would like to know from the hon Minister what is the policy with regard to providing education to the children of those beedi workers who are working in this industry. Sir, coming to recreation part in many States, in many districts of my State, in many constituencies of my district and in many villages of my district, nowhere could I see the receation centres for these beedi workers Sir, it remained on paper. Try to create some recreation centre for the benefit of *(Time-bell)* Sir, I am not making a speech.

MR DEPUTY CHAIRMAN: Your speech is fine but don't repeat the points.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I believe and I think I have touched

MR DEPUTY CHAIRMAN: The problem is, I have a long list.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: I agree, Sir,. .

MR DEPUTY CHAIRMAN: Some Members feel that we are sitting very, very late

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, for the sake of Half-an-Hour Discussion we have been sitting here since morning.

श्री उपसभापति: हर मैम्बर के लिए बोलना नामुमकिन है। We have to be selective.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I am not touching the points which have already been covered by others. Sir, another aspect is, social security. The hon. Minister should explain the aspect of social security for the beedi workers. Now, coming to the Group Insurance Scheme for beedi workers, Sir, all the workers are not covered and the amount assured

for the people who are insured is very meagre. The sum assured is only Rs. 10,000 in the event of natural death and Rs. 25,000 in the event of accidental death. What sort of insurance coverage is this? It is not only meagre but it is not at all helpful to the families. I would like to draw the attention of the hon. Minister to see that, if necessary, the premium may be increased and the employers may be asked to contribute more money for the insurance. Sir, I would like to repeat once again, the premium may be increased by getting more money from the employers and see that sum insured is increased, proportionate to inflation. The other aspect is, in the Fifth Report of the Standing Committee on Labour which was submitted to the Fourteenth Lok Sabha wherein they have stated many surprising things. Many officers say, 'we cannot help, we do not have much staff with us and we agree that we are not maintaining the list of those workers who are working in the residences. We agree that identity cards are not given. We agree that employers are not coming forward to give identity cards.' All those revelations are there in the Standing Committee Report. I would like to draw the attention of the Hon. Minister to this. I believe that he must have gone through the Standing Committee Report. He must have studied. He must have initiated some actions. Let the House know what are the actions contemplated and initiated so far.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Reddy, you have to conclude. Though the speech is fine, it is like a debate. Each Member is taking more time. It is almost a debate. It should not be.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, these are all questions. Finally, Sir, I would like to draw the attention of the hon. Minister towards the enrolment of all the workers who are involved and most important are the people who are collecting tendu leaves. We are not talking about them. Are they part of this Ministry or are they part of the Minimum Wages Act? That should be enlightened. Children, mostly girl children...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All points cannot be covered please. You have taken maximum time. You have taken ten minutes.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, if you are not willing then...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is not the question. I would request you to understand the problem. Everybody wants time. I have no objection.

How long can the House sit? You decide. It is not the Chair who will decide. We have decided half-an-hour, one hour, one and a half hours. There should be some limitation and we have to ration the time

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, kindly give him two more minutes

MR DEPUTY CHAIRMAN: You are making points. I cannot help because sometimes Members feel that the Chair is not giving time, other Members feel that I am giving too much time.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: You have to look at my angle also

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not an individual angle. It is impossible to look at an individual angle Please conclude.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, I tried to draw the attention of the hon. Minister through pointed questions. I did not make elaborate speech. I am in this House for quite some time. I have been observing that Members are getting a lot of time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Again you are saying this. I knew that you are going to say that Members are getting more time. One Member takes time. He will not understand the problem. Then, the other hon. Member feels that what he says is important and what others say is not important. And, it goes on. How, is it possible to control?

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: With due respect to you, Sir, I understand the difficulty. Thank you.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I will take only three minutes. In reply to the question, the hon. Minister has said, 'Accordingly, monitoring or implementation of the minimum wages in respect of beedi workers is done by the respective State Government's.' Sir, it is not only the responsibility of the State Government to implement the minimum wages, but, apart from the State Governments, the primary responsibility also lies with the Central Government. The Central Government has to oversee whether the States are implementing the Act that has been enacted and whether all the provisions are being implemented in right earnest. From time to time, there should be a review by the Labour Ministry. The Ministry has to coordinate with the State Governments and the organisations concerned

and see whether legislation is properly implemented. In this regard, I would like to know from the hon. Minister as to what he is doing on this.

About the evasion of PF, not paying PF and not bringing workers under the purview of the PF, though the State Government has a say in the matter, I would say that it is also the responsibility of the Labour Ministry because you are having a coordinated agency at the Central level. The Central PF Commission, through its various branches in States, has to coordinate. Therefore, the reply given by the hon. Minister shows that he is passing on the responsibility to the State Governments. Therefore, I would like to know how many cases have been filed on the establishments which have not followed the guidelines as far as PF is concerned and whether any action has been taken in this regard.

Then, Sir, a general observation I would like to make. The Labour Department in various States has become a protecting agency of industry. The concept of labour has been ignored. This is my practical experience as a person who is coming from labour side. Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether his Ministry is doing anything in this regard. You have got several agencies, you have several training programmes and you are sending your agents to the States. As far as States are concerned, they should protect the welfare of the labour interests and the labour as a whole. Therefore, the Labour Ministry is there, be it at the Central or the State level. Now, I find that slowly it is becoming pro-industrialist. That attitude has to be changed. I would like to know what the Ministry is doing in this regard. Thank you.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): बस मैं दो मिनट ही बोलूंगा।

श्री उपसभापति: मैं आपसे भी पूछूंगा ...(व्यवधान)

श्री मूलचन्द मीणा: मोटा आदमी है, तोंद बहुत ...(व्यवधान)

श्री उपसभापति: आप बोलिए, आप बोलिए।

श्री मूल चन्द मीणा: उपसभापति महोदय, बीड़ी मज़दूर और बीड़ी कामगार, इनकी समस्याओं के बारे में हाउस के मैम्बर्स ने कई चर्चाएं की हैं। मैं माननीय मंत्री जी से डायरेक्ट कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप बीड़ी मज़दूरों के न्यूनतम मिनिमम वेजेज़ में राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाने के लिए क्या कर रहे हैं? सभी बीड़ी मज़दूरों को प्रतिदिन एक जैसा ही पैसा मिले, आप इसकी क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बीड़ी मज़दूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है? उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, शिक्षा के लिए किताबें, कपड़े व अन्य दूसरी वस्तुएं मिलें, इसके लिए आपका यह मंत्रालय क्या कर रहा है?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि कम्पनी मालिकों के द्वारा जो पी॰ एफ॰ काटा जाता है, इसमें बहुत गड़बड़ी होती है। बहुत सारी शिकायतें स्टेट गवर्नमेंट में हैं क्योंकि गरीब का पैसा काट लिया जाता है और उनको वापिस नहीं दिया जाता है। तो ऐसी शिकायतें आपको मिली हैं तथा उनकी जांच कराई हो तो ऐसी कितनी शिकायतें हैं और कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्यवाही की है?

मेरा अगला प्रश्न बीमा से सम्बन्धित है। बीड़ी मजदूरों को अनेक प्रकार की बीमारियां इस धंधे से होती हैं। उनकी रक्षा के लिए बीमा की क्या व्यवस्था है?

साथ ही यह भी बतला दें कि पिछले दो साल के अंदर कितने बीड़ी मजदूरों की अक्समात् मृत्यु हुई है, क्योंकि इस कार्य से ऐसी बीमारी उनके शरीर के अंदर फैलती है जिससे वे बीमार हो जाते हैं। उनकी रक्षा के लिए, बीमा विभाग से, उनकी कितनी हैल्प कराई है? मेरा एक और निवेदन है कि बीड़ी मजदूरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अस्पतालों की कमी है। आप इस कमी को कब तक दूर देंगे कि वहां अस्पताल खोल दिए जाएंगे, अच्छे डाक्टर्स लगा दिए जाएंगे, एक्सपर्ट डाक्टर्स होंगे। यह सब आप अपने उत्तर में बतला दें, तो अच्छा होगा।

श्री विद्या सागर निषाद (बिहार): उपसभापति महोदय, आज सदन से इन मजदूरों की चर्चा हो रही है, जिन्हें कि इस कार्य से टी॰ बी॰ की बीमारी होती है। सारे देश के पैमाने पर दो ही ऐसे मजदूर हैं जिनको टी॰ बी॰ की बीमारी शतप्रतिशत होती है। उनमें एक तो बीड़ी मजदूर है और दूसरा रिक्शा चालक है। उनकी चर्चा आज सदन में हो, मैं समझता हूं कि जो मजदूर होंगे, उनके दिल दिमाग में वह बात आएगी कि हमारे संबंध में भी हमारे हितैषी सांसद सदन में चर्चा करने के लिए बैठे हैं और उनको इससे भरोसा होगा।

श्री उपसभापति: वह भी देख रहे हैं।

श्री विद्या सागर निषाद: महोदय, हमारे जो माननीय सदस्य इस विषय को लाए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि दीन दुखी की बात आज सदन में आ रही है। उपसभापति महोदय, बीड़ी मजदूरों के संबंध में हमारे माननीय साथियों ने काफी वर्णन किया है। दरअसल में बीड़ी मजदूर, जो बीड़ी बनाने वाले हैं, वे चार बजे भोर में उठते हैं और मिट्टी के तेल के द्वारा वह पत्ता काटा जाता है और पत्ता काट कर के एक घंटा नहीं बल्कि उनका वर्क है 14 घंटा। दूसरे लोग तो 8 घंटे, 6 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे के बाद उनको ओवरटाइम दिया जाता है लेकिन जो बीड़ी मजदूर हैं वे 14 घंटे तक काम करते हैं। हमारे फैक्टरी ऐक्ट के मुताबिक बीड़ी मजदूरों को जो सुविधा

मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पाती, क्योंकि बड़े-बड़े लोग उनको उस रूप में लाते हैं ताकि 20 मजदूर एक जगह संगठित होकर के वे काम नहीं कर सकें। अगर एक ही जगह 20 मजदूरों का रजिस्टर मेन्टेन होता है तो ऐक्ट के मुताबिक उनको सारी चीजें देने का प्रावधान है। लेकिन वहां ठेकेदार के माध्यम से बीड़ी मजदूरों को अलग-अलग डिवाइड किया जाता है और गांवों में जाकर, उपसभापति महोदय, आप भी गांव से आते हैं, बीड़ी मजदूर किस गांव में रहते हैं, कैसे विलेज में रहते हैं वह आप भी जानते होंगे। वे एकदम गंदे गांव में रहते हैं, जंगल में रहते हैं और वहीं वे काम करके किसी तरह से अपनी जीविका को चलाते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे माननीय साथियों ने जो बताया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स देने वाला है, तो वह टैक्स देने वाला है बीड़ी मजदूर। वह टैक्स देने वाला बीड़ी मजदूर है। इसलिए हम बीड़ी मजदूर के माध्यम से तम्बाकू पर टैक्स लेते हैं और उस टैक्स का फायदा हम बीड़ी मजदूरों को नहीं देकर के बड़े-बड़े लोगों को देते हैं, यह बड़े लोगों की पॉकेट में चला जाता है। मैं लेबर मंत्री महोदय से आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरफ मुखातिब होकर के जो मजदूर के माध्यम से टैक्स मिलता है, उस टैक्स के मुताबिक उसको कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए और इस तरह से बीड़ी मजदूरों का उत्थान किया जाये। ....**(समय की घंटी)**...

माननीय उपसभापति महोदय, हमारे साथियों ने मकान के संबंध में बहुत आग्रह के साथ कहा है। मैं चाहता हूं कि जैसे इंदिरा आवास के द्वारा लोगों को मकान दिये जाते हैं, उसी तरह से बीड़ी मजदूरों को भी मकान अनिवार्य रूप से मिलने चाहिए। दूसरी बात मैं सामाजिक सुरक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: आप इनको सुनिये। आप बीच में क्यों बात कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री विद्या सागर निषाद: महोदय, सुरक्षा के नाम पर जो विधवा पेंशन के रूप में दिया जाता है। जो टी॰ बी॰ के पेशेंट हो गये हैं, उनकी उम्र की सीमा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि 40 वर्ष, 60 वर्ष और 65 वर्ष की बात है, जब वह विकलांग हो गया, टी॰ बी॰ पेशेंट जब हो गया, तो उसको सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन होती है, यह अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए।

तीसरी बात मैं हास्पीटल के बारे में कहना चाहता हूं। इसके बारे में हमारे साथियों ने बहुत सी बाते कही हैं। लेकिन बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर आज तक बीड़ी मजदूरों के लिए हॉस्पीटल नहीं है। बीड़ी मजदूरों के लिए स्पेशल हॉस्पीटल होना चाहिए। जहां हॉस्पीटल हैं भी वहां पर मेडिसन नहीं होती हैं, वहां पर दवाएं नहीं होती हैं, इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आप हरेक राज्य के मुख्य मंत्री को, हरेक राज्य के लेबर मिनिस्टर को बुलाकर के विचार-विमर्श करें जिससे कि हर जगह इनके लिए हास्पीटल की व्यवस्था हो सके। ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: आप समाप्त करिये।

श्री विद्या सागर निषाद: उपसभापति महोदय, छात्रों के बारे में भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। फैक्टरियों में कम उम्र के बच्चे काम करते हैं, वहां पर रजिस्टर में उनके नाम नहीं लिखे जाते हैं। फैक्टरी एक्ट की वजह से रजिस्टर मेनटेन नहीं किया जाता है, बीड़ी मजदूर को कोई पहचान पत्र भी नहीं मिलता है।

श्री उपसभापति: श्री विजय दर्डा।

श्री विद्या सागर निषाद: उपसभापति महोदय, एक मिनट।

श्री उपसभापति: जो बात दूसरे मेम्बर्स कह चुके हैं, आप वही बात कह रहे हैं। आप अपनी बात संक्षेप में कहिये।

श्री विद्या सागर निषाद: सर, इसमें चाइल्ड लेबर काम करती है, छोटे बच्चे काम करते हैं, उनको छांट दिया जाता है।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: इसके बारे में दूसरे मेम्बर्स ने कह दिया है।...(**व्यवधान**)...

श्री विद्या सागर निषाद: जो 18 वर्ष से कम उम्र के लडके बीड़ी बना रहे हैं, वे बालिग नहीं हैं, उनको छांट दिया जाता है, वे भी उससे वंचित रह जाते हैं। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए, मैं माननीय लेबर मिनिस्टर से आग्रह करूंगा कि आपके मन में इन गरीबों के प्रति हमदर्दी है ही, आप ऐसे पद पर है कि मात्र यहां से एक बार निर्देश दे देंगे।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: ठीक है, ठीक है। दर्डा जी, आप बोलिये। आप बोलिये। आप बोलिये।... (**व्यवधान**)... आप बैठ जाइये। माफ कीजिए।...(**व्यवधान**)...

श्री विद्या सागर निषाद: आप उसे करने की कृपा करेंगे। नमस्कार।

श्री विजय जे॰ दर्डा (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम हनुमंत राव जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और साथ ही जिन्होंने यह चर्चा प्रारम्भ की है, वे गरीब तबके से हैं, मजदूर हैं जो बीड़ी उद्योग में काम करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि यूपीए सरकार आने के बाद में इस प्रकार की चर्चा हो रही है। मैं महाराष्ट्र प्रदेश से आता हूं, जहां सबसे अधिक बीड़ी मजदूर हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा मजदूर विदर्भ में हैं। बीड़ी मजदूर नागपुर, भंडारा, कांतिनी, वर्धा, यवतनाल, गढ़चिरौली, चन्द्रपुर, नासिक इत्यादी में काम करते हैं। यह कहा गया है 45 लाख के करीब मजदूर इस देश में काम करते हैं। श्री चन्द्रशेखर राव जी, जो हमारे सम्मानीय लेबर मिनिस्टर हैं, वे भी खुद ऐसे जजबात रखते हैं, उनकी जो सोच है, उस सोच को समझ में रखते हुए मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या आप इनकी व्यथा को नहीं जानते हैं? आप जानते हैं। उसके बावजूद भी बीड़ी

वर्कर्स की हालत आज इतनी बुरी क्यों है? आप स्वयं जानते हैं कि बीड़ी वर्कर्स जहां काम करते हैं, वे दो प्रकार के हैं। एक घरों में होता है और एक फैक्ट्रीज में होता है। एक छोटा कॉन्ट्रेक्टर है, एक बड़ा कॉन्ट्रेक्टर है? हजार बीड़ी बनाता है, उसमें से दो सौ रिजैक्ट कर देता है। ऐसी अनेक समस्याएं हैं। मगर मैं उन चीजों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं आपके सामने दो-तीन मुद्दे रखना चाहता हूं। उनमें से एक यह है कि इस उद्योग में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं और महिलाओं के लिए - जो हार्ट, ब्रेन या जो भी बीमारियां इसके अंदर कवर करते हैं, उनमें हार्ट, ब्रेन और टीबी है - लेकिन यूट्रस उसके अंदर सम्मिलित नहीं है। मैं चाहूंगा कि यूट्रस भी उसके अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरा उनके घर के लिए जो 40000 रुपये दिए जाते हैं, उसमें से बीस हजार फ्री हैं लेकिन जब घर के लिए पैसा देते हैं तो उसके अंदर कई चीजें मांगी जाती हैं, जो अनेक प्रकार के सर्टीफिकेट मांगे जाते हैं। - उसके अंदर पीएफ सर्टीफिकेट है, लैंड सर्टीफिकेट है, पोजैशन सर्टिफिकेट है - ऐसे कई प्रकार के सर्टीफिकेट्स हैं। सर, जिनको पीएफ नहीं मिलता हो, वेजिज़ ठीक से न मिलते हों, वे सर्टीफिकेट कहां से लाएंगे? जो घर देने की बात है, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। इसके साथ ही मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि तेलंगाना और विदर्भ, इन दोनों जगहों पर काफी बीड़ी मजदूर हैं। इनमें महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। क्या आप उन्हें मकान देने का प्रोविज़न करेंगे? अगर आप देने वाले हैं तो उसके बारे में बताइए कि कैसे देने वाले हैं। मेरा दूसरा प्रश्न इसके साथ में यह है कि जो कॉन्ट्रेक्ट पर मजदूर काम करते हैं - आप भी जानते हैं, आपका डिपार्टमेंट भी जानता है, इंस्पैक्टर भी जानता है - उसके बावजूद भी वहां पर 14 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे-बच्चियां काम करती हैं। वे वहां पर जाते हैं - क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूं, उस इलाके में बहुत से मजदूर हैं - और जाकर दक्षिणा लेकर वापस आ जाते हैं तथा छांटने के नाम पर, जो बीड़ी अलग करते हैं, उस पैसे को भी वे मांग लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आप सख्त नियम बनाकर अगर इसे कंट्रोल कर सकें--क्योंकि यह विषय तेलंगाना और विदर्भ दोनों का भी है--तो अच्छा होगा। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati N.P. Durga. You have two minutes.

डा॰ प्रभा ठाकुर (राजस्थान): सर, मैं एक मिनट लेना चाहूंगी।

श्री उपसभापति: मैं आपको टाइम दूंगा। मैंने आपका नाम लिखा है। मैंने वादा किया है, मैं आपको टाइम दूंगा लेकिन एक मिनट में ही समाप्त करिएगा।

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Sir, More than 50 per cent of *beedi* workers are women. Many women roll *beedis* with infants on their laps. Both mother and child get smeared with tobacco and they breathe in

tobacco fumes. These women sit in one position for 10 to 16 hours a day to roll *beedis*. Sir, I have to seek three clarifications from the hon. Minister.

Firstly, what is the Government doing to levy tax against unauthorised *beedi* manufacturers to implement uniform wages for *beedi* workers in the country?

Secondly, I would like to know the number of *beedi* workers in the organised and unorganised sectors, covered under the Minimum Wages Act. The hon. Minister had given an assurance to this very House that *beedi* workers working from their residences would also be covered under the Minimum Wages Act. I would like to know what initiative he has taken on this so far.

Finally, there has been a gross misuse of Central Excise Duty exemption given to unbranded *beedi* manufacturers. The Labour Welfare Committee of the Government of India also recommended that exemption granted to unbranded *beedi* manufacturers is counter-productive and should be removed. What has the Ministry done on this so far? Thank you.

डा॰ प्रभा ठाकुर: धन्यवाद उपसभापति महोदय, क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि राजस्थान में भी अजमेर और कोटा में हजारों लोग बीड़ी बनाने का काम करते हैं?

श्री उपसभापति: हर स्टेट में बीड़ी वर्कर्स हैं।

डा॰ प्रभा ठाकुर: मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि एक तो संगठित और असंगठित क्षेत्र में न्यूनतम मज़दूरी में कितना अंतर है, वह क्यों है और किस तरह उसको समान किया जा सकता है? सर, चूंकि सारे बिन्दुओं पर सब लोग बोल चुके हैं--चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, बाल श्रमिक की हो या महिला मज़दूरों के हित की बात हो--जितनी भी बातें सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर रखी हैं, उन सबका लाभ, उन सबके हित के लिए क्या राजस्थान के बीड़ी श्रमिकों को भी ध्यान में रखा जाएगा और क्या उन्हें भी वह सारा लाभ मिलेगा? धन्यवाद।

डा॰ फागुनी राम (बिहार): उपसभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत आभारी हूं।

श्री उपसभापति: आपकी किताब देखते ही मुझे बहुत डर लगता है, आप उसमें से मत पढ़िए।

डा॰ फागुनी राम: मैं उसमें से नहीं पढ़ूंगा। महोदय, बिहार में भी गया में बीड़ी बनती है। पलामू के जंगलों से तेंदुआ पत्तों को काटकर लाते हैं और बीड़ी बनाई जाती है। जिस समय पत्ते लाते हैं, उसी समय से अनहाइजनिक कार्यक्रम शुरू हो जाता है, क्योंकि पत्तों को लाकर वे बड़े-बड़े गोदामों

में एक साथ रख देते हैं और उससे साल भर बीड़ी बनाते रहते हैं। तभी से वहां अनहाइजनिक काम शुरू हो जाता है। जब वे बीड़ी बनाते हैं, तो एक ही पोज़ में बैठकर बनाते हैं, दस-बारह-चौदह घंटे तक उनको बैठना पड़ता है और निकोटीन उनकी सांसों में जाता रहता है। सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि जब वे बीड़ी को सेकते हैं, तो आग के ऊपर जो जाली रखी जाती है, उससे जहरीली हवा निकलती है, जो सीधे उनकी नाक में जाती है और बीमारी पैदा करती है। सर, बीड़ी पीने वाले और बीड़ी बनाने वाले गरीब होते हैं, लेकिन बीड़ी बनवाने वाले ज़रूर अमीर होते हैं। तो उन गरीबों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए, तो हरेक बीड़ी मज़दूर को दो-तीन रोग हो जाते हैं--एक तो उसको श्वास की बीमारी हो जाती है, दूसरा, उसको बैठे-बैठे हड्डी की बीमारी हो जाती है, गटिया या वात जैसा रोग हो जाता है और तीसरी बीमारी, उनको अस्थमा, खांसी या टी॰बी॰ हो जाती है। तो बीड़ी संगठनों में काम करने वाले लोगों के लिए चार-पांच अस्पताल क्या काम करेंगे? आप बताइए। जहां चालीस लाख बीड़ी मज़दूर हैं, पैंतालीस लाख में से चालीस लाख को आइडेंटिटी कार्ड मिला है, पांच लाख मज़दूरों को तो आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं मिला है। जिनको आइडेंटिटी कार्ड मिला है, उन्हीं लोगों की सुविधाओं की बात की जाती है, तो पांच लाख बीड़ी मज़दूर जो ऐसे ही बेकार हो गए हैं जब उनको आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं मिला है तो! इसलिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बीड़ी बनाने वाले कारखाने के मालिक हैं, वे उनको आइडेंटिटी कार्ड दें। वे क्यों नहीं देते हैं? इसका कारण यह है कि लेबर लॉज़ में यह क्लॉज़ है कि अगर इतने मज़दूर काम करेंगे, तो यह लेबर लॉज़ के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए उनकी गिनती नहीं करते हैं। जब दस मज़दूर काम करते हैं,तो वे कह देते हैं कि हमारे यहां दो बीड़ी मज़दूर बीड़ी बनाते हैं। वे इसलिए ऐसा करते हैं ताकि वे लेबर लॉज़ से बच सकें। जब चाहे वे किसी मज़दूर को निकाल सकते हैं और वह मज़दूर लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता है और उसके लिए कठिनाई हो जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके लिए अस्पताल खोले जाएं। सब लोगों ने कहा कि उनके लिए मकान बना दिए जाएं, मैं एक बात कहता हूं कि उनके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि वे अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करते हैं, तो उनके लिए घर भी जो बनाया जाता है, वह अनहाइजनिक होता है, फूस का मकान होता है, मिट्टी तेल की डिबिया से नाक में धुआं जाता है, सीली जमीन में वे बीड़ी बनाते हैं, इसलिए मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से यह सुझाव दूंगा कि इन लोगों की एक निश्चित अवधि पर, एक साल, दो साल या तीन साल में स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। साथ ही एक निश्चित उम्र होनी चाहिए कि इस उम्र तक वे बीड़ी बना सकते हैं। जब वे लोग बीड़ी बनाते-बनाते बेकार हो जाते हैं, तब वे रोगों को लेकर अपने घर चले जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरफ मंत्री जी विशेष ध्यान दें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, I would like to speak for a minute.

7.00 P M

MR DEPUTY CHAIRMAN We have one Member from Karnataka ..*(Interruptions)*.. Mangalore is a very big centre

SHRI JANARDHANA POOJARY Sir, various demands were made inside the Parliament, and outside the Parliament too There were agitations in Mangalore and Udipi, in Karnataka A number of agitations took place They sent some demands to the Ministry I would like to know from the hon. Minister as to what those demands were and what steps the Ministry has taken.

MR. DEPUTY CHAIRMAN Now, the hon Minister to reply

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO Hon Deputy Chairman, Sir, first of all, I appreciate the concern expressed by hon Members about the plight of the poor beedi workers of our country I also share their views with equal emotion, and I thank them for having given me many, many valuable suggestions Sir, I would like to make two or three things very clear here We have to make a clear understanding of certain things While answering the same question in this House, a veteran lawyer, Mr Nariman, I think, he is not here now, was also pointing out that it is a matter of time to take up this matter and debate We always hear from the Government that this is the State Subject. Sir, there are Acts enacted by the very Parliament, this August House It is we who delegated powers to the respective State Governments through the Acts Sir, there are 1492 schedule employments for which the minimum wages are expected to be ensured by the respective Government, that is, the Government of India as far as the 47 schedule employments are concerned Another1445 schedule employments are given to the State Governments where the respective State Governments are expected to ensure the minimum wages as fixed by the Government of India or as fixed by them, as given under the Act and powers for perusal. Section 3 and Section 27 of the Minimum Wages Act, which was brought in by the Parliament, hon. August House, clearly says that this is the duty of the State Government. But, at the same time, I do not deny that we do not have a role Definitely, we have a role. Ours is a federal system. We have a role to play, and I agree and share the views of the hon. Members. In fact, I do not go back to accept that even I am not happy with the way the minimum wages are paid to the poor workers in the country. I am not satisfied and I will not go back to say that. But there are concrete steps

needed to be taken. So, what exactly is to be done, we do discuss with the trade unions, with the employers, time and again. Our Indian Labour Ministry and also the State Labour Ministries mostly function under tripartite culture. I also want to remind hon. Members that we also have a great respect for the International Labour Organisation where we are a founding member, and a permanent member of the ILO. So, we have a lot of respect. Mr. Narayanasamy while referring to the subject, while making his comments, was saying that whether we are labour-friendly or industries-friendly. The UPA Government has very firm determination to be labour-friendly. The UPA Government firmly believes that healthy workforce is the wealth of the nation. People are nowadays talking about labour reforms and I have been very clear at many fora and many daises, and made it very clear that in the absence of a *pucca* safety net, it is impossible to bring in the desired labour reforms. First of all, the safety net of the workers should be thought of and both the things should go hand in hand because without a safety net to bring in stringent labour reforms as expected, as envisaged, are also not correct. It is the firm belief of the hon. Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, and is also the firm belief of the UPA Government. Sir, ensuring the minimum wages, Mr. V. Hanumantha Rao,—thanks to him who brought in this discussion—I would like to tell two, three or four things before I go on to hon. Members' comments. Mainly the beedi workers' welfare was thought of much earlier,but a welfare fund through a cess was thought of in the year 1976 when this Act was brough in. But, unfortunately, that Act started implementing only from the year 1985. Because of the legal litigation, it was locked up in the courts of law till 1985. Ultimately, after the Supreme Court upholding the Act and view of Government, the Government of India started collecting the cess. By the time, I became the Labour Minister, the cess per thousand beedis was only Rs.2.

Sir, with great difficulty, after convincing all the employers, the trade unions and the people concerned, I have taken a daring decision to double it, making it Rs. 4 per thousand. The 'beedi cess' used to be Rs. 85 crores per annum, now it is going to be Rs. 170 crores per annum with which we can definitely expand many, many activities towards the disbursement of money as scholarship to the children of beedi workers; housing conditions can be improved, health care can be improved, certain hospitals can be brought in, and, on the points raised by the hon. Members, there can be a definite scope for the improvement of the schemes.

SHRI JAIRAM RAMESH: Is there an annual statement of how this amount is actually utilised? Sir, can we have an assurance from the Minister as far as this Rs. 170 crores in the Welfare Fund are concerned. Can the Minister tell the House that these are the activities that have been funded, this is how the evaluation is being done, and, this money is actually being utilised for housing, welfare or whatever it is?

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, I thank Mr. Jairam Ramesh for raising this point. He has put in a correct question. This cell is spent under the direction of Ministry of Finance, Department of Expenditure. Any proposal prepared by the Director General, Labour Welfare who works in the Ministry of Labour, is subject to the scrutiny by a Financial Advisor appointed by the Ministry of Finance and the Ministry of Labour. The Financial Advisor scrutinizes everything and prudence is maintained. Annual Accounts are available; Audit Reports are available, and, I will make it available to Mr. Jairam for his perusal.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Are you happy with the utilization of the fund so far? Is the annual average utilization 100 per cent? *(Interruptions)*..

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, my question is not that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I understood your question.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, my understanding is that there is a dedicated Welfare Fund for beedi workers. My question is: whether all the money under that Fund is actually being utilized; and, what are the schemes under which it is utilised? Can an annual report be submitted to the Parliament?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the allocation under each head?

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, I will explain this. I would like to share with the hon. Members as to what actually happened. The concern is very genuine and till now there was a lot of confusion on this subject also. Initially, it was only 20 paise collected for sometime. The money that was coming in was quite meagre. Then, in due course, after so much pressure by the trade unions, workers' agitations--Mr. Janardhana Poojary also pointed it out--it was raised to 50 paise, then again to 75 paise, and, then to one rupee. At one point of time it was doubled to

two rupees, and, Sir, in this financial year, it has been raised to Rs. 4 per thousand There is an accumulated corpus of this Welfare Fund available with the Ministry of Finance, and, I am going to request for release of this amount this year for expanding activities of housing and all that. An amount to the tune of Rs. 54 crores is available with the Ministry of Finance and the amount is spent in this way.

Mainly, the Director General, Labour Welfare in the Ministry implements four, five schemes. Under the scheme of Health Benefits, Rs. 33 59 crores were spent. This is the amount that has been spent in the health sector, to maintain four hospitals. These hospitals are at Mysore, Dhulian, Gurusaiganj and Karma. Three new hospitals are also coming up at Sagar in Madhya Pradesh, Mukkudal in Tamil Nadu, and, Biharsharif in Bihar. 2,206 dispensaries are maintained; there are mobile dispensaries also which go to the rural areas for supply of medicines This is spent on medicines, health check-ups, for conducting health camps, for creating health awareness and all that. We also reimburse whenever there are kidney cases, heart cases or major ailments. There have been cases where an amount of Rs 3 lakhs for one patient has been given. Wherever there was a need of such a great amount, it has been given So, that thing has also been taken care of. Rs. 33.59 crores are spent on health sector. Last year, 3,80,000 students where given scholarships. The State-wise figure is also available with me. Putting Andhra Pradesh and Tamil Nadu together, it was given to 1,09,000 students. In Maharashtra, it was given to 46,180 students. If Karnataka and Kerala put together, it was given to 70,248 students. If West Bengal, Arunachal Pradesh, Assam and Tripura put together, the number is 52,862 scholarships In Bihar and Jharkhand, the number of scholarships distributed is 20,915. In Orissa, it is 22,346. In Uttar Pradesh, it is 15,394. In Rajasthan and Gujarat, the number of scholarships given is 35,628. In Madhya Pradesh and Chhattisgarh, it is 35,628. So, the total number comes to 3,80,733 scholarships.

डॉ॰ प्रभा ठाकुर: सर, मंत्री जी ने राजस्थान, गुजरात सब एक साथ कह दिया है, राजस्थान में कितना है, गुजरात में कितना है, यह बताइए।

श्री उपसभापति: वह बता देंगे।

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Let me complete, please. So these are distributed. On assuming the charge of the Labour Ministry, I for one,

was doubting over the distribution of scholarship, whether it was proper or not. Because, with the skeleton staff, the Zonal Welfare Officers, who are in-charge of two big States, whether they are doing it properly or not. As mentioned by so many Members, I have to share my feelings with them, as mentioned by my elder colleague, my respected colleague, Mr.Nandi Yellaiah, I was six-time MLA in the Siddipet constituency where every alternative house makes *bidis*. The constituency which I represent in the Lok Sabha now, Karimnagar district, that constitutes the largest number of bidi workers in Andhra Pradesh. So, I am fully exposed; I am fully aware of the problems of these bidi workers. So, when my Director General (Labour Welfare) explained to me that they were distributing those many number of scholarships in the State of Andhra Pradesh, I had my own doubts and I requested three District Collectors, without telling the DG (LW) to enquire into the matter through RDOs & MROs and submit me a report. And, Sir, I really feel happy that all the scholarships which were distributed, were found to be genuine. I have the report of the District Collector office. I have the official report with me. It was found to be genuine. That is how it is being done.

Then, Sir, previously, housing was very poor. My friend, Shri Chandra Sekar Reddy has also asked me how many houses have been constructed all over the country for the bidi workers. The situation is very poor. The number is very poor. Only one lakh five thousand and odd number of houses have been constructed. Nothing more than this. Previously, the housing scheme, which was meant for the bidi workers, was very complicated. But, I have totally changed it. Recently the hon Finance Minister has also approved it. Now, the scheme is going to be very straight. It will be implemented through the State Governments, by the District Collectors, as the ILO scheme is implemented. It is taken away from the Welfare Commissioners because they do not have much of the staff with them and they cannot look into the whole issue. That is the reason I thought we could give it to the State Governments which will get it implemented through the District Collectors. They will send the proposal and they will send the scheme.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But, the components are very complicated.

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: I have removed all that, Sir. I will explain it Previously, it was 50 per cent grant and 50 per cent loan and all

that. So many complications were there. But now, this scheme is going to be very straight. The beneficiary needs to have only three things. Number one, either the provident fund number or the identity card given by the Director General (Labour Welfare) That is the first thing. Secondly, he should possess a house site, either provided by the Government, if they are weaker sections people, or,

श्री नंदी येल्लैया: आप जो प्रॉविडेंट फंड स्कीम की बात कर रहे हैं, यह स्कीम भारत सरकार की है लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत है कि ...(व्यवधान)

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO. Let me explain please. I will, explain, Sir. First let me explain this housing scheme. The new housing scheme is going to be like this The worker should possesses only three things. That is, they should have the provident fund number or the identity card given by the Labour Welfare Commissioner. Number two, they should have a house site held by them, either of their own, or given by the State Government. And, number three, they should deposit Rs. 5,000 and the Government of India will give Rs. 40,000 as grant, which is not a loan at all, which is not recoverable. With those Rs. 45,000 the house can be constructed.

I think this goes well with us. There was a meeting of Secretaries which has come to this conclusion and the Ministry of Finance is also going to approve the scheme very shortly. I think, by the end of this month, we will be communicating this to all the State Governments across the nation. This is the new housing scheme. I think this will be definitely flexible which will enable the workers to construct their houses. The housing expenditure last year was only 13 per cent out of Rs. 88.88 crores that means only Rs. 11.49 crores; this year, it is going to increase substantially. I think, we are going to spend Rs. 100+crores because the major concentration of beedi workers is, starting from the East, in the States of Orissa, West Bengal, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and down south, Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. This is the major concentration. In other States also, there are beedi workers, but the number is not that high as that of the mentioned states.

As far as social security is concerned, as Mr. Chandra Sekar Reddy was also referring to this, a group insurance scheme was brought in.

The beedi workers are actually assessed to be more than 60+lakhs. But as mentioned by Mr. Pillai, the identity cards are issued only to 41 lakh people. We have to issue identity cards to the remaining workers. We are taking necessary steps, we are sending special teams and I also assure the hon. Members since I know the plight of the beedi workers personally as I come from that area. I fully share the sentiments which have been expressed by the hon. Members and I will make all special efforts to help these poor beedi workers to the best of my ability and capacity. The provident fund, as mentioned by Shri Nandi Yellaiah,....*(Interruptions)*.... The sum assured is very meagre.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is saying that he will take steps.

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: The very welfare cess started flowing in from the year 1995 only and at the initial stages, it was quite meagre, the insurance money, the group insurance money, every year, Rs. 60 are deposited. I would definitely examine the aspect of increasing the premium, if it is possible. I cannot assure right now, but I will definitely examine the matter whether this cess can be increased.

श्री नंदी येल्लैया: सर, क्या इसका कोई नियम है? क्या फैक्टरियों में काम करने वालों के लिए प्रोविडेंट फंड का कोई नियम है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: नियम है न ...(व्यवधान)...

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: I am coming to that.

श्री नंदी येल्लैया: आपकी सरकारी मशीनरी वहां नहीं पहुंच रही है। उसका क्या हो रहा है?

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: He is coming to that point ...(*Interruptions*)...

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, the provident fund coverage to the beedi workers was 17,96,358 workers in respect of 4,158 establishments. Recently, after my assuming charge as the Labour Minister, I have received some complaints from West Bengal and other places From January to March, we have conducted a special drive. Out of which, 47,087 workers are brought under the provident fund coverage and I have sent a special team to West Bengal from Delhi. We have raided about 7 to 8 major companies which are evading the provident fund. Now, the assessment is going on. The expectation of coverage is going to be about

additional 17,000 beedi workers very shortly I will also inform the hon. Members. So, this is the effort made. Still I am not satisfied, Sir. The workers are very poor, they are exposed to hazardous disease. Sir, some Members said that they were overtapped, it is not correct because the workers who make beedi in their houses, they combine their works For some time, they take care of their children, and whenever they feel free, दो घंटे का जो समय मिलता है, उसमें बीड़ी बनाता है, फिर उसके बाद दूसरा काम करते हैं। It is a typical mixed kind of thing So, the question of minimum wages is also of a great concern, as mentioned by almost all Members The hon. Members, Shri K. Chandran Pillai, was telling that the minimum wages are very meagre *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN That was the major concern expressed by all Members. *(Interruptions)*

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO. So far as the States of Jharkhand and Arunachal Pradesh are concerned, I assure Mr. Pillai and I also assure the House that I will send special teams to jharkhand and Arunachal Pradesh as early as possible, to take stock of the situation. *(Interruptions)*

SHRI DATTA MEGHE You send these teams to Vidharba also. *(Interruptions)*

MR DEPUTY CHAIRMAN: Yes, yes. He will send them to all places. *(Interruptions)* एक-एक स्टेट के बारे में वह कैसे बोलेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री के॰ चन्द्रशेखर राव: मेरा जवाब पूरा करने का बाद भी आप पूछेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। I will come to that. Since Mr. Pillai has said that in Jharkhand, the minimum wage is only Rs. 20/- or Rs. 22/- per day, which is really very meagre, and the situation is really very painful. He made a mention that in Arunachal Pradesh, it is Rs. 31/- only. So, I thought that there is a special need to take care of this aspect. If any hon. Member is interested to bring out any specific problem to my notice, I will not hesitate to take action, and this time, within a week, I will send a special team from Delhi. I assure you that I will see to it that something is done. I will take it up with the respective Chief Ministers myself. I will talk to them and see what best can be done. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, we will take 7.30 p.m. as the deadline for completing this debate.

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, as far as the default in provident fund by the establishments is concerned, which is also a much-believed and much-propagated issue, luckily, it is not much in the beedi sector. Only eleven establishments are defaulting to the tune of Rs. 5,85,00,000/-, and efforts are afoot to recover the default amount also.

डा॰ फागुनी राम: सर, एक बात पूछनी है।

श्री उपसभापति: वह अभी reply कर रहे हैं, आप बीच-बीच में मत बोलिए। लिखकर रख लीजिए।

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, some Members were saying that in the State of Andhra Pradesh, the minimum wage is only Rs. 55/- per day. But according to the latest information furnished by the Government of Andhra Pradesh, Rs. 85.10 per day has been fixed as the minimum wage. But as expressed by the hon. Members, whether the State Government is really ensuring that Rs. 85.10 minimum wage per day is being given to the beedi worker or not, is the moot question. The hon. Members have brought the issue to my notice. I will definitely examine it. I assure the Members that I will try to do what best can be done. The concern of Shri Nandi Yellaiah...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Yellaiah, the hon. Minister said that he will examine it. You have brought it to his notice. He will examine it. *(Interruptions)*

श्री नंदी येल्लैया: सर मिनिस्टर साहब, reply कर रहे हैं तो क्या हम हकीकत नहीं बोलेंगे? मेरा मेन क्वैश्चन है जिसकी वजह से half an hour discussion हो रहा हैं।

श्री उपसभापति: Half an hour की बात छोड़ दें, यह डेढ़ घंटे का डिस्कसन हो गया है।

श्री नंदी येल्लैया: सर, यह फैक्ट है।

श्री उपसभापति: आपने फैक्ट बोल दिया, उन्होंने कहा कि I will get it examined.

श्री नंदी येल्लैया: सर, मैं बोल रहा हूं कि मिनिमम वेज 85 रुपए है, लेकिन उसका implementation नहीं हो रहा है।

श्री उपसभापति: उन्होंने कहा कि examine कराऊंगा।

डा॰ फागुनी राम: सर, एक नया पॉइंट उठाना चाहता हूं।

श्री उपसभापति: ऐसे नहीं होगा, साढ़े 7 से पहले complete करने दीजिए।

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: Sir, there is a bit of confusion as far as the minimum wage is concerned. In some States, the wage is fixed per day. In some States, the wage is fixed on monthly basis, that is, 1,000/- and some odd rupees. How many thousands are made in one day? It is a typical thing. Anyway, I share the concern of the hon. Members. I admit, I confess it to the House that even I am not happy with what is happening. much scope is there for improvement in ensuring the minimum wages. I will take all possible measures to the best of my capacity. *(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is an omnibus reply. *(Interruptions)*

SHRI K. CHANDRA SEKHAR RAO: If any specific complaint is brought to my notice by any Member...*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister has said that he himself is not satisfied with the situation. He will consider all the suggestions made by the hon. Members carefully and will take all precautionary measures. Now, the House is adjourned to meet tomorrow at 11 o'clock.

The House then adjoruned at twenty-five minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Friday, the 13th May, 2005.